

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/57/2018

प्रवेश तिथि
11-05-2018

निर्णय दिनांक
08-08-2018

01- शर्माखिलाड़ी पुर नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम नैथला तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राज०
अपीलान्ट

बनाम

01- तहसीलदार, मालाखेड़ा, जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा
दिनांक 12.01.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू०
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 92/2017

उपस्थित:-

01- श्री गोविन्द राम यादव

-वकील अपीलान्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 12.01.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नैथला की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 848 रकबा 0.36 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यक्ति होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलाब किया गया।

पिटान अभिभाक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नैथला की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 848 रकबा 0.36 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी मना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 05.04.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2018 में देवादेत आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है एवं तहसीलदार मालाखेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वह मौका परीक्षण कर एवं यदि अतिक्रमण यथावत पाया जाता है अथवा अपीलान्ट उक्त आराजी से मुक्त अतिक्रमण करता है, तो उसके विरुद्ध एल आर एक्ट के तहत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08-08-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओपी० जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)